been taken up. And we will be trying to pass these projects as early as possible. If my friend has any suggestion to make, he can do so.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Under the sub-plan for the tribal areas, is there any major and medium projects proposed to be taken up there before the end of the 5th Plan?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: For major and medium irrigation projects taken up in 1977-78 alone, we have an outlay of Rs. 31 crores; and for minor irrigation projects Rs. 29 crores; and the total amounts to Rs. 60.43 crores.

DR. HENRY AUSTIN: Is the government aware of the fact that although 4 crores of tribal people are involved, irrigation facilities available to them come to hardly I per cent out of the total 28 per cent allotted so far? Is government taking some interest in providing irrigation facilities to the tribal people in the Malanad area under the Malanad Development Scheme? The Malanad Development Scheme covers States covered by the Western Ghats. It is an important scheme of the Central Government. Maharashtra, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu are the States concerned. Have irrigation facilities been provided under this scheme? The Minister said that under various schemes, it is being contemplated. Can he enlighten us further in this regard?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I have got the State-wise Plan outlays, and State-wise figures for 1977-78 also. Maharashtra, total outlay Rs. 5 crores, Kerala Rs. 3 crores and Karnataka Rs. 4 crores. I have got all these facts.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या माननीय मन्त्री जी बतलाएंगे कि बिहार में आदिवासियों के रहने का जो एरिया है उसका क्षेत्रफल क्या है और अभी तक उन लोगों के लिए वहां सिंचाई की क्या व्यवस्था की गई है ? अगर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई और उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ तो क्या फिर से इसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे कि उसका सर्वेक्षण करके उनके लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाय ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं पूरा क्षेत्रफल तो नहीं बता सकूंगा लेकिन मैं यह बताऊंगा कि सबसे ज्यादा खर्चा इसके ऊपर बिहार में ही किया जा रहा है । मेजर और मीडियम इर्रीगेशन के लिए 9 करोड़ 65 लाख रुपया और माइनर इर्रीगेशन के लिए 8 करोड़ 61 लाख रुपया यहां खर्च किया जा रहा है । कुल मिला कर 18 करोड़ 26 लाख रुपया उस एरिया में खर्च किया जा रहा है ?

DR. SAROJINI MAHISHI: Allocation of the money does not mean utilization of the money for the purpose for which it is meant. How much of the money allotted for this purpose, *i.e.* for increasing irrigation facilities, has been utilised in the tribal areas? For question 606 also, when there was a question of irrigated land in Gujarat, a similar answer was given. How much of the money was actually utilised?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: It was only in the 5th Plan that money was provided to the tune of Rs. 65 crores in the first 3 years. We will have to assess the utilization of all that. For the remaining 2 years of the Plan, I have stated that Rs. 125 crores are being provided.

प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना समिति

*612. **श्री यदराज :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोफसर एम० एल० दांतवाला की अध्यक्षता में गठित की गई प्रायोगिक

गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना सम्बन्धी समीक्षा समिति ने प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार परियोजना के प्रभाव की जांच करने और देश के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में पाम रोजगार सम्बन्धी उपयुक्त आदर्शों का सुझाव देने के बारे में विभिन्न अनुसन्धान और शैक्षणिक संस्थाओं को अध्ययन कार्य सौंपा था;

(ख) क्या समीक्षा समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है और इसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं और इसे कब तक कार्य रूप दे दिया जयेगा ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes Sir. However, the precise name of the scheme was "Pilot Intensive Rural Employment Project".

(b) The Review Committee on P.I.R.E.P. has finalised its report and it is expected to be submitted to Government soon.

(c) Does not arise.

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रो० एम० एल० दांतवाला की अध्यक्षता में जो एक्सपेरिमेन्टल इन्टेन्सिव रूरल एम्पलायमेन्ट प्रोजेक्ट की समीक्षा समिति गठित हुई थी और उस समीक्षा समिति ने परियोजना के प्रभाव की जांच करने और देश के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में ताड़ रोजगार सम्बन्धी आदर्शों का सुझाव देने के बारे में जो अनुसन्धान और अध्ययन कार्य किया, उस की रिपोट कब आई ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने इसके बारे में मालूम किया है उम्मीद है इस महीने के आखिर तक आ जायगी ।

श्री युवराज : इस समीक्षा समिति को यह काम कब सौंपा गया था ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 10 अक्तूबर, 1974 को ।

श्री युवराज : समीक्षा समिति को जो रिपोर्ट आने वाली है--उस पर कितना रुपया खर्च हुआ और उन्होंने कितना वक्त लगाया ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा । अभी पूरा ब्यौरा मेरे पास नहीं है ।

श्री ईश्वर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश में पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया था, उस की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि ताड़ से सम्बन्धित जितने भी मनुष्य लगे हुए हैं, उन का बहुत ह्रास हो रहा है । देश में इस से दो हज़ार क्विंटल अनाज प्रतिवर्ष बचाया जा सकता है । क्या मंत्री महोदय इस महत्वपूर्ण प्रश्न की दृष्टि में रखते हुए उस प्रति वेदन को मंगवा कर अध्ययन करेंगे ताकि इस से देश में अन्न की वृद्धि हो, बचत हो और गरीबों का संरक्षण हो--क्या आप इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेंगे

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं उस रिपोर्ट को मंगवा कर अध्ययन कर लूंगा । लेकिन यह सवाल इस सवाल में एराइज़ नहीं होता है ।

Per Hectare yield of Crops

*614. SHRI S. KUNDU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether per hectare yield of rice and paddy and other crops is going down in some States;

(b) if so, names of such States and the comparative figures of per hectare yield in different States;

(c) steps taken to increase the yield; and